



e-ISSN:2582 - 7219



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 6, Issue 1, January 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.54



6381 907 438



6381 907 438



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com



कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण विकास के बीच संबंधों का भौगोलिक अध्ययन

Geographical study of the relationship between agro-based industries and rural Development

डॉ. सुनील कुमार, सह आचार्य ¹ डॉ. पुष्पा, सहायक प्रोफेसर ²
भूगोल विभाग, आईएएसई मानित विश्वविद्यालय सरदारशहर (राज.)
जीव विज्ञान विभाग आईएएसई मानित विश्वविद्यालय सरदारशहर (राज.)

Dr. Sunil Kumar ¹ Dr. Pushpa ²

Associate Professor Department of Geography, IASE, (Deemed to be University) Sardarshahar (Raj)
Assistant Professor, Department of Zoology IASE (Deemed to be University) Sardarshahar (Raj)

सार संक्षेप

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में कृषि के विकास को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो गया है। किन्तु आज भी कृषक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का कारण मूलतः कृषि सम्बन्धित निर्णयों में उसकी भागीदारी का अभाव तथा दूसरी ओर प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। कृषि व औद्योगिक विकास होगा तो स्वाभाविक ही ग्रामीण विकास होगा। कृषि आधारित उद्योग सामान्यतः वे उद्योग होते हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें कृषि कच्चे माल के साथ-साथ कृषि के आदानों के रूप में जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक, विनिर्माण और प्रसंस्करण गतिविधियों को शामिल किया गया है। ग्रामीण परिदृश्य में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इसलिए ग्रामीण विकास का आधार है। कृषि आधारित उद्योग जो इस प्रमुख ग्रामीण आर्थिक गतिविधि पर पनपते हैं, ग्रामीण विकास में भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं

मुख्य शब्द – ग्रामीण, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास

परिचय

ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से गांवों का आर्थिक उत्थान एक महत्वपूर्ण विचार बन गया। इसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि निर्माण इकाइयों का विकास, कृषि – सेवा इकाई द्वारा ग्रामीण देश के सभी हिस्सों के लिए एक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से बिजली का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और



संचार प्रौद्योगिकी के सभी विस्तार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। परमाणु प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और अवज्ञा प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का विकास। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास में इसके महत्व को देखते हुए वर्तमान अध्ययन सूक्ष्म स्तर का अध्ययन है। कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों, कृषि – उत्पाद निर्माण इकाइयों, कृषि आदानों, विनिर्माण इकाइयों और कृषि सेवा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

कृषि – प्रसंस्करण उद्योग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कृषि वस्तुओं को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करते हैं जो उत्पाद में मूल्य जोड़ते हैं। " कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। कृषि – प्रसंस्करण उद्योग, विशेष रूप से खाद्य निर्माण, तंबाकू और कपड़ा प्रसंस्करण, वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्र पर हावी हैं। इस अर्थ में कृषि – प्रसंस्करण को एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और संचालन के लिए और इसे भोजन, चारा, फाइबर, ईंधन या औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकी आर्थिक गतिविधियाँ। इसलिए, कृषि – प्रसंस्करण उद्योग। गुंजाइश फसल से सभी कार्यों को शामिल करती है फसल के अंत तक चरण। सामग्री वांछित रूप, मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य में अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती है। प्राचीन भारतीय शास्त्र भोजन और औषधीय उपयोग के लिए कृषि उपज के संरक्षण का उल्लेख करते हैं और इसका विस्तृत विवरण है प्रसंस्करण के लिए कटाई के बाद और प्रसंस्करण प्रथाओं लेकिन, अपर्याप्त ध्यान अतीत में कृषि – प्रसंस्करण क्षेत्र ने उत्पादक और उत्पादन दोनों को नुकसान पहुंचाया वह उपभोक्ता और इसने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। .

प्रसंस्करण उद्योग का विकास



भारत में कृषि – प्रसंस्करण उद्योग राष्ट्रीय आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्थानीय जरूरतों और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम , और सड़क और दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से बिजली आपूर्ति के मामले में इस उद्योग के लिए सहायक बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से स्थापित है। ग्रामीण कारीगरों और उपयोगकर्ताओं के लिए विनिर्माण (उपकरण बनाने , वेल्लिंग) में अच्छी तरह से स्थापित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं। हालांकि , इस क्षेत्र को वर्तमान में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन , स्थानीय और विदेशी वित्त दोनों तक पहुंच को लेकर मौजूद अनिश्चितताओं , सीमित शोध , सीमित तकनीकी सलाह , सीमित विपणन जानकारी और विश्वसनीय बाजारों की कमी से उत्पन्न कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। .

कृषि उद्योग कृषि उत्पादों जैसे कृषि फसलों , वृक्ष फसलों , पशुधन और मत्स्य पालन के प्रसंस्करण में मदद करता है और उन्हें भोजन और अन्य उपयोगी रूपों में परिवर्तित करता है। निजी क्षेत्र को अभी तक कृषि उद्योग की पूरी क्षमता का एहसास नहीं हुआ है। चीनी , कॉफी , चाय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे सॉस , जेली , शहद आदि के लिए वैश्विक बाजार बहुत बड़ा है। प्रसंस्कृत मांस , मसालों और फलों का बाजार भी उतना ही बड़ा है। केवल आधुनिक तकनीक और गहन विपणन के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ ही घरेलू बाजार के साथ – साथ निर्यात बाजार का भी पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि खाद्य निर्माता बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं , प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण , नवाचार और कृषि – उत्पादन में नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकी के समावेश को संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के साथ समझें , भारत और दुनिया में कृषि उत्पादों की कुल उत्पादन क्षमता अगला है। दशक तक दोगुना होने की संभावना है। इसके अलावा , फल प्रसंस्करण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए 2005 में एक विजन , रणनीति और कार्य योजना की स्थापना की थी। उद्देश्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण



के स्तर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, मूल्यवर्धन को 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और वैश्विक खाद्य व्यापार की हिस्सेदारी को 1.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना है। कृषि में मशीनीकरण अथवा उन्नत तकनीकी का प्रयोग बुद्धिमता पूर्ण कार्य है, जो कृषकों के द्वारा परम्परागत कृषिगत क्रियाएं आधुनिक क्रियाओं में बदल जायें, यह मात्र एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि दीर्घकालिक प्रक्रिया है। कृषि यंत्रीकरण में ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। कृषि – उद्योग में मुख्य रूप से मध्यवर्ती या अंतिम उपभोग के लिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और संरक्षण की कटाई के बाद की गतिविधियाँ शामिल हैं। यह दुनिया भर में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त तथ्य है, विशेष रूप से औद्योगिक विकास के संदर्भ में, कृषि – उद्योगों का महत्व कृषि के सापेक्ष बढ़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 'भोजन' केवल उत्पादन नहीं है। भोजन में प्रसंस्कृत उत्पादों की एक विस्तृत विविधता भी शामिल है। इस अर्थ में कृषि उद्योग विकासशील देशों में विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्सा है और औद्योगिक क्षमता निर्माण का साधन है।

कृषि आधारित उद्योग

कृषि एवं औद्योगिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं कृषि के बिना उद्योग धन्धों का विकास नहीं हो सकता और उद्योग धन्धों के बिना कृषि का समुन्नत विकास हो पाना असम्भव है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि कृषि उद्योग धन्धों के बीच समन्वय होना अति आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है अतएव क्षेत्र की अयोजना में कृषि नियोजन महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों ने कृषि नियोजन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। वस्तुतः कृषि नियोजन सम्पूर्ण कृषि समुदाय को उत्पादन की ओर अग्रसर कर आर्थिक वृद्धि के एक उच्च दर को प्राप्त करने का प्रयास होता है। कृषि विकास योजना में क्षेत्र की उपलब्धता सुविधा के आधार पर निर्णय लेने पर बल प्रदान किया जाता है। कृषि नियोजन द्वारा भूमि की प्रत्येक इकाई के अनुकूलतम उपयोग को निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य से नियोजन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवं संशोधन की सुविधा के साथ ही समयानुसार बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में उसमें परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है।¹

ग्रामीण विकास संकल्पना की वास्तविक रूपरेखा का अभ्युदय कब हुआ, इस संदर्भ में निर्दिष्ट एवं प्रामाणिक रूप में कुछ कहना, करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी ऐसा विवास



किया जाता है कि प्राचीन काल में क्षेत्र के विद्यमान संसाधनों के आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन आमतौर पर एक उपागम के रूप में अपनाया जाता था।² सामाजिक, आर्थिक उन्नयन एवं संरचनात्मक परिवर्तन हेतु पूर्व नियोजन की प्रक्रिया एक अभिनव उपागम है जो मूलतः समाजवादी राष्ट्रों की देन है।³ भारत में योजनाबद्ध ग्रामीण विकास की शुरुआत वर्तमान सदी में ही की गयी। इसका प्रारम्भिक श्रेय रवीन्द्रनाथ टैगोर को जाता है जिन्होंने 1920 ई. में शान्ति निकेतन के पास स्थित कुछ गांवों के विकास हेतु योजना बनाई। महात्मा गांधी ने इसे अधिक यथार्थवादी रूप प्रदान किया, जब उन्होंने ग्रामीणों के आपसी सहयोग और सद्भावना से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का सुझाव दिया है। इसी के तहत 1948 ई. में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में पाइलट प्रायोजना की शुरुआत की गई जो देश की ग्रामीण नियोजन की प्रथम प्रायोजना कही जा सकती है इस प्रायोजना में मेयर महोदय⁴ ने ग्रामीण नियोजन के कतिपय आधारभूत मुद्दों; अच्छा आवास, विकसित परिवहन एवं संचार तंत्र, ग्रामीण उत्पादों की नियमित और शीघ्र खपत, जल आपूर्ति एवं सिंचाई व्यवस्था और स्कूल, अस्पताल आदि खोलने पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। दुबे⁵ ने 1958 ई. में सामुदायिक विकास हेतु कृषि कार्य, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, समाज कल्याण एवं गृह सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा प्रस्तुत की। इसके बाद लाटन⁶ ने 1959 ई. में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों पर तथा नाजियुल करीम⁷ 1967 ई. में समाज में व्याप्त कमियां, जो आर्थिक सामाजिक उन्नयन में बाधक के नियन्त्रण पर बल दिया।

1967 ई. में आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिफार्म कमेटी के सुझाव पर कृषकों के तत्कालिक आवश्यकता एवं विकास के लिए लघु एवं सीमान्त तथा कृषि मजदूर विकास एजेन्सी गठित की गयी। इसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा भूमि विकास के लिए विभिन्न सुविधायें की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर बढ़ाने हेतु तैयार की गयी नीतियों के अन्तर्गत (1) आर्थिक वृद्धि (2) कृषि का आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं (3) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रहा।

ग्रामीण विकास का केन्द्रीय लक्ष्य एक ऐसे विकास की प्रक्रिया का प्रारम्भ करता है जो लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सके और उनके लिए अधिक समूह और विभिन्नता पूर्ण जीवन की व्यवस्था कर सके। यह नियोजन तार्किक ढंग से भारतीय ग्रामीण विकास की विभिन्न समस्याओं का हल ढूँढता है, ग्रामीणों के बीच व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करता है। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति नियोजन के अभाव में सम्भव नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी वरीयताएं रखी गयी है। यह नियोजन प्रजातांत्रिक ढंग से राजकीय निर्देशन में हो रहा है ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में निम्न प्रविधियों का प्रयोग हुआ है (1) संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन (2) मूल्य नीति के द्वारा साधनों का वितरण (3) पूंजी संग्रह व साख व्यवस्था का विकास (4) वित्तीय नीति का एक यंत्र के रूप में प्रयोग तथा (5) विभिन्न विकास स्तरों पर नियंत्रण। अकाल जांच आयोग (1944) ने कहा कि कृषि आधारित उद्योग



वे हैं जो न केवल राज्य के औद्योगीकरण में सहायता करते हैं बल्कि खेतों के उत्पादों को संभालने के अलावा कृषि आदानों के साथ खेतों की आपूर्ति में भी शामिल हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (1965) ने "कृषि आधारित उद्योग" को परिभाषित किया है, जो अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए कृषि कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इनमें बीज, उर्वरक, उपकरण, पौध सुरक्षात्मक रसायन आदि शामिल हैं। इनमें केवल वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि कृषि उपकरणों और मशीनरी की मरम्मत और सर्विसिंग भी शामिल है। कृषि आधारित उद्योगों को परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, पूंजी निवेश, रूपांतरित तकनीकी जटिलता परिवर्तन की डिग्री के अनुपात में बढ़ जाती है। कच्चे माल या भोजन को बदलने का उद्देश्य प्रयोग करने योग्य रूप बनाना, भंडारण क्षमता को बढ़ाना, अधिक आसानी से परिवहन योग्य रूप बनाना, और पौष्टिकता या पोषण गुणवत्ता को बढ़ाना है।

कृषि आधारित उद्योग अपने कच्चे माल की तीन विशेषताओं के कारण अद्वितीय हैं : (ए) मौसमी , (बी) खराब होने और (सी) परिवर्तनशीलता। लेकिन सभी कृषि आधारित उद्योग इन विशेषताओं को समान रूप से साझा नहीं करते हैं

परिवर्तनशीलता

कृषि उद्योगों में कच्चे माल की मात्रा और गुणवत्ता में परिवर्तनशीलता होती है। मौसम में उतार-चढ़ाव, मिट्टी की स्थिति आदि के कारण मात्रा अनिश्चित है। मानकीकरण के कारण गुणवत्ता भिन्न होती है, कच्चे माल की मायावी बनी रहती है, भले ही पशु और पौधों के आनुवंशिकी में प्रगति हुई हो। ये विविधताएं उत्पादन, शेड्यूलिंग और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित संचालन के संदर्भ में कृषि-औद्योगिक इकाइयों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं।

कृषि आधारित उद्योगों के प्रकार

कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि वे विदेशी



मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और देश को भुगतान संतुलन की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तीन समूह शामिल हैं। पहले समूह में प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां मुख्य रूप से चावल मिल, दाल मिल, तेल मिल आदि शामिल हैं। दूसरे समूह में पारंपरिक खाद्य इकाइयों, फलों, सब्जियों और मसालों की प्रसंस्करण इकाइयों सहित असंगठित कुटीर उद्योग शामिल हैं। अंतिम समूह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का संगठित क्षेत्र है जिसे आगे निम्नलिखित उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है :

- (अ) प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण
- (ब) फल और सब्जियां प्रसंस्करण
- (स) डेयरी और लाइव स्टॉक उत्पाद
- (द) मछली और मछली उत्पाद
- (ड) उपभोक्ता सामान उद्योग

हर साल लाखों गरीब परिवार काम की तलाश में पलायन करते हैं। गांवों में आजीविका के धराशायी होने के कारण वे पलायन को मजबूर हैं। ये संकटग्रस्त प्रवासी अक्सर अपने घरों को बंद कर लेते हैं, कुछ मामूली सामान ले जाते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं। अपने माता-पिता के साथ जाने वाले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 14 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 9 हर साल लाखों होने का अनुमान है। अपने गाँव से दूर होने के कारण, वे उन जगहों से संबंधित नहीं होते हैं जहाँ वे जाते हैं और तेजी से अपने ही गाँवों में स्वीकृति खो देते हैं। वे अपने समुदाय, संस्कृति और परंपराओं से अलग हो गए हैं, त्योहारों, मेलों, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने में असमर्थ हैं, जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार उनकी पहचान की भावना खो देते हैं। राज्य की सीमाओं को पार करने वाले लोगों की भेद्यता और भी अधिक है क्योंकि वे खुद को अपने ठेकेदारों की दया पर अधिक से अधिक पाते हैं।

परंपरागत रूप से, किसान प्राकृतिक संसाधनों, श्रम, कौशल और ज्ञान के साथ-साथ अपने निवेश का उपयोग करके या तो अपनी बचत या वित्तीय ऋण से खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादक होते हैं। लेकिन कुछ किसान दूसरों की तुलना में गरीब हैं। आमतौर पर वे भूमिहीन किसान होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों की जमीन किराए पर देनी पड़ती है या दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं। कृषि उत्पादों को आमतौर पर स्थानीय बिचौलियों या दलालों को निर्देशित किया जाता है, जो कभी-कभी बड़े राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को वितरित करने से पहले किसानों को ऋण और बंधी हुई शर्तों के साथ उत्पादन के कारक प्रदान करते हैं। ये लोग फिर उत्पादों



को बाजारों में बेचेंगे। इस बाजारोन्मुखी ढांचे के तहत ज्यादातर किसान कीमत लेने वाले होते हैं। दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर उनकी सौदेबाजी की शक्ति कम होती है जैसे कि बहुत जल्दी या देर से मौसम या उस अवधि के दौरान जहां आपूर्ति की कमी होती है। बाजार की मांग का जवाब देने की आवश्यकता है, लेकिन कोई सीधी पहुंच नहीं है, 4 आसानी से खराब होने वाले उत्पादों से निपटना और ऋणी होना इस कम सौदेबाजी की शक्ति में योगदान करने वाले प्रमुख कारक हैं।

वर्तमान परिपेक्ष में –

वर्तमान में कॉर्पोरेट ने उत्पादन पक्ष को नियंत्रित करने में एक प्रमुख हिस्सा ले लिया है। कॉर्पोरेट द्वारा कृषि आमतौर पर बड़े पैमाने पर होती है और राष्ट्रीय बाजारों या बाहरी बाजारों तक सीधी बाजार पहुंच होती है। कई कॉर्पोरेट को स्थानीय बिचौलियों द्वारा कृषि उत्पादों की आपूर्ति की जाती है जबकि अन्य का किसानों के साथ सीधा अनुबंध हो सकता है। मालिकों और कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों के लिए, कृषि सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र है और उनकी मुख्य चिंता उनकी आजीविका का एक अभिन्न अंग होने के बजाय हानि, लाभ और वित्तीय लाभ के बारे में है। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर कृषि की स्थिति के बारे में चर्चा करते समय, आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न खिलाड़ियों, कॉर्पोरेट, बिचौलियों और छोटे और मध्यम किसानों के बीच अंतर करना चाहिए— ताकि उन पर प्रभाव और किसी विशेष स्थिति के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को उनके संदर्भों के तहत स्पष्ट रूप से समझा जा सके। और वर्तमान बाजार संरचनाएं। समायोजन खाद्य आपूर्ति खाद्य मूल्य छोटे पैमाने पर कृषि उत्पादन व्यवसाय, लाभ, आदि। संसाधन आधार जैसे। बीज, पानी, भूमि, जंगल, जैव विविधता, आदि। कॉर्पोरेट कृषि मूल्य, जीवन का तरीका, संस्कृति, सामाजिक संबंध, आय, आदि।

निष्कर्ष

वर्तमान स्वरूप एवं ग्रामीण विकास के दृष्टिगत चयनित किया गया हैं वस्तुतः विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कृषि एवं औद्योगिक विकास विचार के वि”लेषण के लिए आन्तरिक एवं वाह्य गुणकों को सम्मिलित किया जाता है। सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन क्षेत्र के दृष्टिगत जिन



विचरों का चयन किया गया है उनमें कृषि एवं औद्योगिक विकास के विभिन्न पक्षों को समाहित करने का प्रयास किया गया है।

1. कृषि गहनता
2. शुद्ध कृषित क्षेत्र
3. कृषि उत्पादकता
4. शस्य गहनता
5. पशुपालन
6. वाणिज्यिक शस्य
7. शिक्षित जनसंख्या
8. कार्यशील जनसंख्या
9. विद्युतीकरण
10. कृषि मशीनीकरण
11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
12. सेवा केन्द्र
13. लघु उद्योग धन्धे
14. परिवहन
15. कच्चे माल की आपूर्ति सेवा क्षेत्र
16. वित्तीय सेवा केन्द्र
17. जलपूर्ति केन्द्र
18. संचार के साधन
19. शीत ग्रह केन्द्र
20. शक्ति संसाधन केन्द्र

उपरोक्त 20 विचर जो कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास से जुड़ हुये हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् दोनों के बीच समन्वय है। उपरोक्त विचरों के द्वारा ग्रामीण विकास के स्तर का निर्धारण विभिन्न शोधों में किया गया है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय आबादी का लगभग 65% हिस्सा सीधे कृषि पर निर्भर करता है और यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22% है। कृषि का महत्व इस तथ्य से प्राप्त होता है कि इसका विनिर्माण क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति और मांग संबंध हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र ने खाद्यान्न , तिलहन , वाणिज्यिक फसलों , फल , सब्जियां , खाद्यान्न , मुर्गी पालन और डेयरी के उत्पादन और उत्पादकता में शानदार प्रगति देखी है। भारत काजू और मसालों का सबसे बड़ा विदेशी निर्यातक होने के अलावा दुनिया में फलों और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने टारगेट को हासिल करने में लगातार काम कर रही है. उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग और फूड सप्लाय



चेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. सबसे बड़ी बात ये है कि देश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों का बागवानी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके एक्सपोर्ट का असर सीधे किसानों की जेब पर पड़ता है. और अगर बागवानी में एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले 5 सालों के दौरान 39-5 मिलियन टन के इजाफे के साथ बागवानी उत्पादन अब तक के हाई रिकॉर्ड 320-48 मिलियन टन पर पहुंच गया है.

संदर्भ –

1. Journal of the Association of North Indian Geographers Vol. 36, No. 1 June 2006, pp. 136.
2. Prakash Rao, V.L.S. (1963) Regional Planning Theoretical Approach, Calcutta, P. 5.
3. Kuklunski, A.K. (1978), Some Basic Issues in Regional Planning and National Development in Mishra R.P. et. Al. (eds.) Vikas Publication, New Delhi, pp.5.
4. Mayer, A. and Associate (1959) : Pilot Project India the study of Rural Development of Etawah, Uttar Pradesh Univ. of California Press, Berkeley and Los Angeles, 367.
5. Dubey, S.C. (1958) India's Changing Villages, Bombay.
6. Lawtan, G.H. (1958-59), India's Changing Villages, Royal Geographical Society of Australia South Australian Branch paer (60), P. 17-24.
7. जे विल्किंसन और आर रोचा , " द एग्रो-प्रोसेसिंग सेक्टर: अनुभवजन्य सारांश , हालिया रुझान और विकास प्रभाव" , अंतर्राष्ट्रीय कृषि-उद्योग फोरम के लिए व्यापक पेपर , नई दिल्ली , अप्रैल 2008 ।
8. खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) , वैश्विक संगठन , " सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिति में कमी के लिए कृषि-व्यवसाय का महत्व" , संपत्ति विकास पर विश्व संगठन आयोग के लिए चर्चा पत्र , सोलहवां सत्र , न्यूयॉर्क , मई , 5 – 16 , 2008.
9. ए.ओ. |कमसरं " खाद्य निर्माण में सामग्री उत्पादकता" , यांक जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल सोशल साइंस , वॉल्यूम। 74, नंबर 1, फरवरी 1992, पीपी. 177-185 ।
10. आर.ई. लोपेज , " कनाडाई खाद्य प्रक्रिया उद्योग के भीतर आपूर्ति प्रतिक्रिया और निवेश" , अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल सोशल साइंस , वीओ। 67, नंबर 1, फरवरी , 1985, पीपी. 40-47 ।
5. एस.एम. डाइट्ज़ और एस. मती , एसेसमेंट ऑफ़ द स्मॉल स्केल फूड प्रोसेस सब सेक्टर इन तंजानिया और अफ्रीकी राष्ट्र , आईएसबीएन , 2000 ।



INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor
7.54

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com